



IMPORTANT SECTIONS

Partnership Act 1932

PRAGGYA INSTITUTE

यहाँ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

(Indian Partnership Act, 1932)

के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्षंस की सूची जिनसे न्यायिक परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं:

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932)

(Judicial Exams में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले सेक्षंस)

1. आधारभूत परिभाषाएँ और सिद्धांत (Basic Definitions and Principles)

* धारा 4: भागीदारी, “भागीदार”, “फर्म” और “फर्म नाम” की परिभाषाएँ

* Section 4: Definition of “partnership”, “partner”, “firm” and “firm name”

* यह अधिनियम की नींव है और इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।

* धारा 6: भागीदारी के अस्तित्व को अवधारित करने का तरीका

* Section 6: Mode of determining existence of partnership

* यह सेक्षन भागीदारी की आवश्यक विशेषताओं (जैसे लाभ साझा करना और आपसी अभिकरण) पर आधारित है, और केस लॉ के साथ बहुत महत्वपूर्ण है।

* धारा 7: इच्छाधीन भागीदारी

* Section 7: Partnership at will

* इच्छाधीन भागीदारी की परिभाषा और उसका विघटन।

2. भागीदारों के संबंध (Relations of Partners)

* धारा 9: भागीदारों के सामान्य कर्तव्य

* Section 9: General duties of partners

* सद्भाव और ईमानदारी के कर्तव्य पर आधारित।

* धारा 13: पारस्परिक अधिकार और दायित्व

* Section 13: Mutual rights and liabilities

* लाभ/हानि का वितरण, पूँजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज जैसे वित्तीय पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण।

* धारा 14: फर्म की संपत्ति

* Section 14: The property of the firm

* यह समझना कि क्या फर्म की संपत्ति बनती है।

3. तीसरे व्यक्तियों से संबंध (Relations with Third Parties)

* धारा 18: भागीदार फर्म का अभिकर्ता होगा

* Section 18: Partner to be agent of the firm

* भागीदार के एजेंसी संबंध को स्थापित करता है, जो बाहरी लोगों के साथ व्यवहार में महत्वपूर्ण है।

* धारा 19: फर्म के अभिकर्ता के रूप में भागीदार की विवक्षित प्राधिकार

* Section 19: Implied authority of partner as agent of the firm

* भागीदार के निहित अधिकारों और उसकी सीमाओं को समझना।

* धारा 25: फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व

* Section 25: Liability of a partner for acts of the firm

* भागीदारों के संयुक्त और पृथक् दायित्व को स्पष्ट करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

* धारा 26: भागीदार के दोषपूर्ण कार्यों के लिए फर्म का दायित्व

* Section 26: Liability of the firm for wrongful acts of a partner

* भागीदार के गलत कार्यों के लिए फर्म की देनदारी।

* धारा 28: धारित किए जाने का सिद्धांत (Holding out)

* Section 28: Holding out

* यह सिद्धांत उन लोगों की देनदारी से संबंधित है जो भागीदार न होते हुए भी खुद को भागीदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

* धारा 30: भागीदारी के लाभों में अवयस्कों का प्रवेश

* Section 30: Minors admitted to the benefits of partnership

* न्यायिक परीक्षाओं में यह सबसे अधिक पूछे जाने वाले सेक्शंस में से एक है। अवयस्क के अधिकार, देनदारियां और वयस्क होने पर उसके विकल्प।

4. आने वाले और जाने वाले भागीदार (Incoming and Outgoing Partners)

* धारा 31: भागीदार का प्रवेश

* Section 31: Introduction of a partner

* नए भागीदार के प्रवेश और उसके दायित्वों पर।

* धारा 32: भागीदार का निवृत्त होना

* Section 32: Retirement of a partner

* निवृत्त होने वाले भागीदार के अधिकार और विघटन के बाद की देनदारी।

* धारा 35: मृत भागीदार की संपदा का दायित्व

* Section 35: Liability of estate of deceased partner

* मृत भागीदार की संपदा की देनदारी कब समाप्त होती है।

5. फर्म का विघटन (Dissolution of a Firm)

* धारा 39: फर्म का विघटन

* Section 39: Dissolution of a firm

* विघटन की परिभाषा।

* धारा 40: करार द्वारा विघटन

* Section 40: Dissolution by agreement

* आपसी सहमति से विघटन।

* धारा 42: कुछ आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन

* Section 42: Dissolution on the happening of certain contingencies

* विशिष्ट घटनाओं पर विघटन।

* धारा 44: न्यायालय द्वारा विघटन

* Section 44: Dissolution by the court

* विघटन के लिए न्यायालय में आवेदन के आधार (जैसे पागलपन, कदाचार, स्थायी अक्षमता)। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्षण है।

* धारा 45: विघटन के पश्चात् किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व

* Section 45: Liability for acts of partners done after dissolution

* विघटन के बाद भी बाहरी लोगों के प्रति दायित्व।

* धारा 48: भागीदारों के बीच लेखाओं का निपटारा करने का तरीका

* Section 48: Mode of settlement of accounts between partners

* विघटन पर खातों का निपटारा कैसे किया जाता है, यह एक प्रक्रियात्मक और महत्वपूर्ण सेक्शन है।

6. फर्मों का रजिस्ट्रीकरण (Registration of Firms)

* धारा 69: रजिस्ट्रीकरण न होने का प्रभाव

* Section 69: Effect of non-registration